श्री नवाबसिंह चौहान : इसकी किस तरह से अदायगी होगी, या एडजस्टमेंट होगा ?

श्री एन० कानूनगो : एडजस्टमेंट यही होगा कि बर्मा सरकार जो लाइसेंस इश्यू करेगी वह हिन्दुस्तान में खरीदने वाले खरीद लेंगे और उसका रुपया यू० एस० ए० के अकाउंट से पेमेंट होगा ।

*201. [*Withdrawn.*]

परमाण्विक गवेषणा संस्था का खोला जाना

*३०२. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या परमाणु शक्ति विभाग को हैदराबाद की साइन्स सोसाइटी की ओर से एक परमाणिवक गवेषणा संस्था खोलने के सम्बन्ध में कोई योजना प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ?

†[OPENING OF AN INSTITUTE OF NUCLEAR RESEARCH

*302. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state whether the Department of Atomic Energy have received any scheme for opening an Institute of Nuclear Research from the Science Society of Hyderabad? If so, what are its salient features and what decision has been taken in that regard?]

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : हैदराबाद साइन्स सोसाइटी ने हैदराबाद में न्यूक्लियर रीसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने की तजवीज रखी थी । इस इंस्टीट्यूट का इन्तजाम एक गवर्निंग बोर्ड करेगा, जिसमें परमाणु शक्ति विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद साइन्स सोसाइटी और आन्ध्र प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे । सोसाइटी ने यह भी तजवीज रखी कि वह जो धन स्वयं इकट्ठा करेगी उससे तथा भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों (ग्रांटों) से इंस्टीट्यूट की माली सहायता करेगी ।

यह मामला परमाणु शक्ति विभाग के पास विचार के लिये भेज दिया गया । उस विभाग की राय यह थी कि ठोस कार्य तभी किया जा सकेगा जब कि प्रस्तावित इंस्टीट्यूट, उस्मानिया विश्वविद्यालय के साथ मिला दिया जाय । जब ऐसा आश्वासन मिल जायेगा तो इंस्टीट्यूट को सहायता देने के सवाल पर विचार किया जायेगा ।

†[THE DEPUTY MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI LAKSHMI MENON): The Hyderabad Science Society proposed to set up an Institute of Nuclear Research in Hyderabad. This was to be managed by a Governing Board consisting of the representatives of the Department of Atomic Energy, Osmania University, Hyderabad Science Society and the Government of Andhra Pradesh. The Society proposed to finance the Institute from funds raised by it and grants from the Government of India and the State Government.

The matter was referred to the Department of Atomic Energy. The Department was of opinion that significant work could only be done if the proposed Institute was integrated with the Osmania University. When an assurance to this effect is received, the question of giving assistance to the Institute will be considered.]

श्री नवाबसिंह चौहान : किस तरह की, किस नेचर के, रिसर्चेज इस इंस्टीट्यूट में किये जायेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट में न्यूक्लियर रिसर्चेज किये जाते हैं, आम तौर से । मेरी समझ में नहीं आता

†[ ] English translation.

क्या जवाब दूं कि किस ढंग के होंगे । यह तो मुनहसिर है इस पर कि उनके पास कितना सामान है, कितना इक्विपमेंट है । अगर उनके यहां साइक्लोटोन ज्यादा है तो ज्यादा कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं । पहली बात यह है कि उसमें एक बुनियादी तालीम होगी और गीलिबन जो इक्विपमेंट है उस पर एक्सपेरीमेंट होंगे ।

श्री नवाबसिंह चौहान : जैसा कि माननीय डिप्टी मिनिस्टर ने उत्तर में बताया है, जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी उसको स्वीकार कर लेगी, रिकग्नाइज कर लेगी उस वक्त सहायता देने के सवाल पर विचार किया जायेगा, तो क्या यह ठीक है कि इस वक्त तक उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने उसको रिकग्नाइज कर लिया है ? अगर हां, तो आप क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह काम—न्यूक्लियर रिसर्च करना—ऐसा है, जाहिर है, कि हर एक आदमी इसको करना चाहे तो मुनासिब नहीं है कि उसको मौका दें जिससे ख्वाहमख्वाह रुपया जाया हो और काम न हो लेकिन हम इस रिसर्च के काम को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिये हमने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जहां साइंस डिपार्टमेंट अच्छा है उससे इसका सम्बन्ध हो तो ठीक है । उसमानिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम अपने केम्पस में जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन हम जिम्मेदार नहीं होंगे उसमें क्या काम होता है । यह मामला है । तो हमने उन से कहा आप जिम्मेदारी ले ली जये उसकी कार्यवाही की तो अच्छा है, तब हम मंजूर करेंगे ।

श्री नवाबसिंह चौहान : क्या सरकार की तरफ से या एटामिक इनर्जी कमिशन की तरफ से कोई जांच पड़ताल की गई है कि कितना इक्विपमट सोसाइटी के पास है, कितना नहीं है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन उन्होंने उस पर गौर करके जवाब दिया और वह आपको बता दिया गया ।

SHRI V. C. KESAVA RAO: What is the financial assistance given to this research institute?

SHRI JAWAHARLAL NEHRU: I don't know. I don't think any assistance has been given. The question has not arisen yet.

SHRI M. H. SAMUEL: May I know whether there is any information of the work done by the society previously on this subject?

SHRI JAWAHARLAL NEHRU: Personally I have none. I have no such information. I don't know if some other Department of the Government possess some information.

VISIT OF LAW MINISTER TO REFUGEE CAMPS IN WEST BENGAL

*303. SHRI BHUPESH GUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether he is aware that the Minister of Law visited a number of refugee camps in West Bengal to persuade the refugees to go to Dandakaranya;

(b) if so, whether the rehabilitation of displaced persons is the responsibility of the Ministry of Law; and

(c) if the answer to part (b) above be in the negative, for what special reasons the Minister of Law undertook the above task which concerns another Ministry?

THE DEPUTY MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI LAKSHMI MENON): (a) Yes. The